WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

Conversion of 'Similipahar' in Orissa as a National Padk

*132. SHRI BASUDEB MOHAPATRA: Will the Minister of ENVIRONMENT AND FORESTS be pleased to state:

(a) what is the number of National Parks at present in the country and whether Government have any programme to add to the number of such Parks during the Seventh Five Year Plan Period;

(b) if so, what steps have been taken by Government to convert 'Similipahar' in Orissa as a National Park; and

(c) what is the total acreage of land to be covered under this project and also the number of species to be kept in this Park?

THE MINISTER OF ENVIRONMENT AND FORESTS (SHRI Z. R. ANSARI): (a) There are 66 national parks in the country at present. The subject of creation of national park vests with the State Governments.

(b) and (c) The 'Similipahar' (Similipal) Sanctuary was established in 1979 covering an area of 2200 sq. kms. Notification with respect to establish a national park on 845 sq. kms. was issued in two stages in 1980 and 1986. The estimated population of important animal species found in the park is given below:—

Name of species	Estimated population
TIGER	89
PANTHER	185
ELEPHANT	450
GAUR	350
WILD DOG	50
SAMBAR	7,000
CHITAL	500
CHAUSINGA	1,000
BARKING DEER	5,000
MOUSE DEER	4,600
WILD BOAR	9,500
COMMON LANGUR	10,000
CROCODILE	86

पर्यावरणीय दृष्टि से परियोजनाओं की स्वीकृति के सम्बन्ध में केन्द्र द्वारा जारी किया गया निर्देश

*185. श्री सुरेन्द्र सिंह ठाकुर
सरदार जगजीत सिंह अरोड़ा:

क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या यह सच है कि अनेक औद्योगिक, सिंचाई संबंधी और अन्य बहुद्देश्यीय परियोजनाएं लम्बे समय से पर्यावरणीय दृष्टि से स्वीकृति हेतु लंबित पड़ी हुई हैं ;

(ख) क्या यह भी सच है कि सरकार ने इस आशय का एक निदेश जारी किया है कि संबंधित अधिकारी को अधिकाधिक चार महीने की अवधि के अन्दर-अन्दर किसी परियोजना का अनुमोदन अथवा निरनुमोदन करना होगा;

(ग) यदि हां, तो 30 सितम्बर, 1988 को चार महीने से अधिक समय से ऐसी कितनी परियोजनाएं स्वीकृति हेतु लम्बित पड़ी हुई थीं ; और

(घ) इस संबंध में विलम्ब से निर्णय लेने वाले संबद्ध अधिकारियों के विरुद्ध सरकार क्या कार्यवाही करने का विचार रखती है ?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री जेड० आर० अंसारी) : (क) जी, हां।

(ख) से (घ) एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है।

विवरण

(ख) लंबित मामलों की जांच करने से पता चला है कि इनमें से अधिकांश मामले परियोजना प्राधिकारियों से पूरी सूचना प्राप्त न होने के कारण लम्बित हैं। अब यह निर्णय लिया गया है कि परियोजना प्राधिकारियों द्वारा भेजी गई सूचना में पाई गई कमियों को उन्हें सूचित किए जाने की तारीख से तीन महीने के भीतर यदि पूरी सूचना नहीं भेजी जाती है तो प्रस्ताव को नामंजूर किया समझा जाएगा तथा परियोजना प्राधिकारियों को तदनुसार इस निर्णय के बारे में